दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज पर लेवी 1 अप्रैल, 1981 से लगा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम ने समाचार पत्रों से मार्च 1981 से ही लेवी वसूल करना क्यों प्रारम्भ कर दिया ;

(ग) क्या छोटे तथा मध्यम श्रेणी के पत्रों से वसूल की गई लेवी की राशि उनको छूट दिए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें वापस कर दी गई है ;

(घ) यदि "नहीं" तो उपर्युक्त श्रेणी के कितने समाचार पत्रों की कितनी-कितनी राशि अभी तक वापस नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार समाचार पत्रों को उनके द्वारा जमा कराई गई राशि पर ब्याज देने का विचार रखती है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। अखबारी कागज पर 1 मार्च, 1981 से मूल्यांकन 15 प्रतिशत की दर से आयात शुल्क लगाया गया था।

(ग) छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों के मामले में जिनका वर्गीकरण भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा किया गया है, उनके वापसी दावों की पुष्टि में दस्तावेज मिल जाने पर भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा वापसियों की अदायगी की जा रही है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी, नहीं।

Research Development and Design Institute for Aluminium

883. SHRI DHARAMCHAND JAIN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 769 given in the Rajya Sabha on the 24th February, 1981 and state the progress so far made in implementing the proposal for the setting up of a Research, Development and Design Institute for Aluminium Industry?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): Further progress made in implementing the proposal for setting up of a Research Development and Design Centre for Aluminium is as under:—

The proposal for getting UNDP/UNIDO Assistance for preparation of a feasibility Report for the proposed Centre has since been accepted and the perparatory Assistance document has been signed betwen Government of India and UNDP in June, 1981. Following this, steps necessary for the preparation of the feasibility report have been initiated.

Bank Credit to Sick Industrial Units

884. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the State-wise number of sick (1) large-scale and (2) small-scale industrial units as at the end of 1980-81;

(b) what is the total amount of credit advanced by Commercial banks to large-scale and small-scale sick units to-date;

(c) how many of the sick large scale and small scale units are economically viable; and

(d) what is the programme of the Government relating to the revival of the viable sick units?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): (a) The latest state-wise information